Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 60102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

संपादन की अवधारणा

डॉ. साधना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

संपादन एक व्यापक शब्द है। अकसर संपादन का अर्थ समाचारों को काट–छाँट कर, कितनीं जगह में, किस जगह या पृष्ट पर देना है आदि के रूप में लिया जाता है। परन्तु संपादन अपने संपूर्ण अर्थ में पत्रकारिता के संपूर्ण कलेवर से जुड़ा है। संपादन एक विविध चरणों में पूर्ण होने वाली गंभीर और लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कोई समाचार, लेख, फीचर, साक्षात्कार आदि प्रकाशन और प्रसारण के लिए भेजे जाते हैं । संपदान की प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा उसमें जरूरत के अनुसार संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन किया जाता है।

मीडिया चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक उसकी पहुँच और प्रसारकक्षेत्र बहुत विशाल एवं विस्तृत होता है। अतः इसमें संपादन कार्य का महत्व बहुत बढ़ जाता है क्योंकि एकतो जनसंचार माध्यमों में सूचना का प्रवाह बहुत तीव्र होता है, दूसरे उनके प्रभाव के दूरगामी परिणाम होते हैं। यदि सूचना के प्रेषण से पूर्व ध्यान न दिया जाये और गलती से कोई ऐसी सूचना निष्कासित हो जाए जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो तो यह बहुत नुक्सान कर सकता हैं। यद्यपि स्वयं संवाददाता भी प्रत्येक घटना की सूचना सोच–समझ कर संप्रेषित करता हैं परन्तु घटना की जानकारी तुरंत देने की शीघ्रता में कुछ तथ्य अनदेखे भी रह जाते हैं। उस परिस्थिति में संपादक सूचना को काट–छाँट कर, तराश कर और चमका कर जनता तक पहुँचने के काबिल बनाता है।

संपादन की अवधारणा के संदर्भ में यदि हम आज पत्रकारिता की स्तिथि पर दृष्टि डालते हैं तो इस क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। प्रसार बढ़ा है विस्तार के साथ–साथ विविधता भी आई है। पत्रकारिता को एक व्यवसाय के रूप में देखे जाने से उसमें जटिलता आई है। उसके साथ ही संपदान का काम भी उतना सीधा और सरल नहीं रह गया है जितना पहले था। आज आदर्श निष्ठा आस्था का स्थान व्यापक दृष्टि विस्तृत अध्ययन सामान्य ज्ञान की भंडारण क्षमता अंग्रेजी भाषा का ज्ञान तुरंत फैसले लेने की सामर्थ्थे तथा जबरदस्त बाहरी दबावों के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता संपादन कार्य को सफलता प्रदान करती

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

है। संपादन आज समय प्रबंधन भी है क्योंकि तेजी से प्रवाहित होती सूचनाओं को इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा के बीच निरन्तर संप्रेषित करना उचित प्रबंधन के द्वारा ही संभव है।

इससे पता चलता है की पत्रकारिता में संपादन का बहुत महत्व है। संपदान के पशचात आलेख का स्वरूप पहले जैसा नहीं रहता वरन उसे एक नई पहचान और छवि मिलती है। प्रारंभ में संपादन का संबंध केवल मुद्रित माध्यमों से यथा समाचारपत्र पत्रिका आदि से था लेकिन वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे टीवी रेडियो आदि पर भी संपादन कार्य करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मुद्रित माध्यमों में संपादक होते हैं उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी होते हैं।

संपादन का कार्य एक कठिन और गंभीर तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी का काम है। वृहत हिंदी कोश के अनुसार संपादन का अर्थ होता है पूरा करना प्रस्तुत करना ठीक प्रकार से कार्य को अंजाम देना ग्रंथ या आलेख जो शुद्ध करके उसे प्रकाशन योग्ये बनाना अथवा किसी समाचारपत्र समूह का ठीक प्रकार से सञ्चालन करना । मैन्सफील्ड का मानना है कि स्वीकृत एवं सुन्दर ढंग क्रमबध्द पठनीय आकर्षक रूप और सजावट के विविध तरीकों के आधार पर उपसंपादक संपादन करता है।

वस्तुतः संपादन का कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता विशेष रूप से आज के समय में जब पत्रकारिता का अपना आकार प्रकार अत्यंत विस्तृत हो चूका है तब तो यह असंभव ही है। इसलिए संपादन कार्य के लिए एक पूरा संपादकीय विभाग अथवा संपादन कक्ष होता है जिसमें अनेक लोग अपनी पदेन स्तिथि में इस कार्य को करते हैं। इनमें संपादक सह–संपादक समाचार–संपादक विचार–संपादक मुख्य उपसंपादक तथा उपसंपादक होते हैं। ये सभी संपादन के कार्य को संपूर्ण तथा उत्कृष्ट बनाने के लिए अपनी पूरी योग्यता के अनुरूप कार्य करते हैं।

समाचार को प्रकाशन या प्रसारण योग्य बनाने में संपादन कि बहुत अहम भूमिका होती है। यद्यपि प्रत्येक माध्यम में समाचार के संदर्भ में रिपोर्टिंग विभाग अलग से कार्य करता है परन्तु सम्यक रूप से देखने पर वह संपादकीय विभाग का ही हिस्सा होता है जिसका प्रमुख संपादक होता है। समाचार पात्र पत्रिका रेडियो और टेलीविजन सभी में संपादक ही इस बात का निर्णय करता है कि कौन सी सामग्री छापी जाएगी अथवा रेडियो टीवी पर क्या सुनाया और दिखाया जाएगा।

प्रत्येक सूचना माध्यम में सुबह को सम्पादकीय विभाग कि एक बैठक संपादक की अध्यक्षता में की जाती है और तय किया जाता है कि कौन सी खबर किस प्रकार देनी है। अगले दिन के पूरे अखबार का प्रारूप तैयार किया जाता है। टीवी में भी यह निर्णय लिया जाता है कि कौन–कौन सी घटनाओं को कवर किया जाना है। संपादकीय बैठक में ही यह तय होता है कि सम्पादकीय किस विषय पर लिखा जायेगा। संपादक की यह जिम्मेदारी भी होती है कि वह सूचना और व्यावसायिकता के मध्य संतुलन स्थापित करे। उदाहरण

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 60102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

के तौर पर समाचार पत्र अथवा न्यूज चौनल में विज्ञापनों की संख्या को नियंत्रित करना संपादन की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी प्रकार एकाधिक संस्करण निकालने वाले अखबारों में स्थानीय संस्करण का संपादन कार्य स्थानीय संपादक करता है परन्तु अखबार की नीति मुख्यालय में प्रमुख संपादक ही निर्धारित करते हैं। समाचार संपादन से जुड़े अधिकांश कार्य मुख्य उपसंपादक या उनकी टीम द्वारा किए जाते हैं।

अखबार के दफ्तर में दिन–रात काम चलता रहता है और सबसे अधिक काम उपसंपादक को करना पड़ता है। संपादन की प्रक्रिया में समाचार के सभी विवरण संकलित करना भाषिक गलतियाँ सुधारना शीर्षक लगाना लीड तथा अन्य प्रमुख समाचारों का क्रम तय करना अनुवाद कार्य करना आदि सम्मिलित हैं। उसी प्रकार टीवी में भी मुख्य उपसंपादक और उपसंपादकों द्वारा संपादन कार्य किया जाता है। विशेषज्ञान के इस युग में खेल फिल्म वाणिज्य आदि से संबंधित विशेषज्ञ उपसंपादक नियुक्त किए जाते हैं।

प्रिंट मीडिया का तो पृष्ठ सुनिशचित रहता ही है परन्तु न्यूज चौनल में खेल वाणिज्य आदि संपादक ही तय करते हैं कि खेल वित्त व्यापर उद्योग आदि की खबरें कैसे कब और किस रूप में देनी है। आजकल पत्रकारिता का उद्देश्य सूचना पहुँचना ही नहीं है वरन मनोरंजन करना भी है। मीडिया में साहित्यिक रचनाएँ भी छापी जाती हैं न्यूज चौनल तथा मनोरंजन चौनल भी फिल्म सीरियल आदि का प्रसारण करते हैं। संपादन कार्य की पहुँच उन सभी प्रकाशनों और प्रसारणों तक होती हैं तभी ये सारी सामग्री व्यवस्थित और प्रभावी रूप में पाठक दर्शक वप्रोता तक पहुँच पति है।

इस प्रसंग में संवाददाता और उप–संपादक की भूमिका को समझाना आवश्यक है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर माने जाते हैं।जो पत्रकार घटना की कवरेज करते हैं उन्हें संवाददाता और जो डेस्क पर बैठ कर प्राप्त कॉपी में काट–छाँट सुधार करके उनका संपादन करते हैं उन्हें उपसंपादक कहा जाता है।उपसंपादक ही कॉपी संपादक भी होता है। किसी भी कॉपी संपादक में कुछ विशिष्ट गुणों का होना जरूरी है अन्यथा वह अपने काम को बखूबी नहीं कर पायेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समाचार भिन्न–भिन्न विषयों की सूचना देते हैं अतः उनका संपादन करने वाले को अधिकांश विषयों की थोड़ी–बहुत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उसके अतिरिक्त भाषा पर अधिकार समाचार की चेतना की पकड़ विवेचन–विश्लेषण की क्षमता मीडिया कानून की जानकारी तथा त्वरित निर्णय लेने की सामर्थ्य भी संपादन कार्य करने वाले के लिए जरूरी विशेषताऐं हैं।

यद्यपि प्रस्तुति से पूर्व प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादन की प्रक्रिया में बहुत से कार्य एक समान होते हैं फिर भी श्रव्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों की अपनी आंतरिक बनावट और प्रणाली की दृष्टि से इस प्रक्रिया में कई परिस्थितियों में अंतर भी रहता है। इसलिए रेडियो टीवी में भी संपादक द्वारा समाचारों तथा अन्य कार्यक्रमों को प्रसारण से पूर्व संपादित किया जाता है। रेडियो और टीवी में भी अंतर है क्योंकि रेडियो श्रव्य

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

माध्यम होने के कारण उसके द्वारा संप्रेषित कार्यक्रमों को केवल सुना जा सकता है जबकि टीवी के कार्यक्रमों को देखा और सुना जाता है। टेलीविसिओं में दृश्यात्मकता का गुण एक ओर उसके कार्यक्रमों की ग्रहणशक्ति को बढ़ता है दूसरी ओर उसका जनता पर पड़ने वाला प्रभाव भी अन्य सभी माध्यमों से अधिक होता है । रेडियो के संदेशों को प्रसारित करने की क्षमता भी बहुत विस्तृत होती है अतः दोनों ही माध्यमों द्वारा प्रसारित सूचनाएँ बिना पूरी जाँच–परख के संप्रेषित नहीं की जा सकतीं ।

रेडियो श्रव्य माध्यम होने के कारण उसमे ध्वनि संगीत और प्रभावशाली आवाज वाले वक्ता का बहुत महत्व है। इसके अलावा समय की सीमा होने के कारण संक्षिप्तता का भी पालन करना पड़ता है। इसके लिए संपादक को इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि समाचार–वाचक निश्चित अवधि में ही समाचार पढ़ कर समाप्त करदे साथ ही इस बात का भी पहले से ही ध्यान रखा जाता है कि पूरी सूचना श्रोता तक पहुँच जाए। इसी प्रसंग में भाषा की दृष्टि से भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है।

रेडियो के कार्यक्रमों की भाषा सहज सरल तथा बोलचाल में प्रचलित शब्दों से युक्त होनी चाहिए जिससे एक बार सुनते ही श्रोता सन्देश को ग्रहण कर ले उसे अर्थबोध के लिए किसी प्रकार की व्याख्या अथवा अन्य साधन की जरूरत न पड़े। उसके लिए जरूरी है कि संपादन के समय ही उन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाए। रेडियो समाचारों का चयन शीर्षक या हेडलाइन देना और समाचार वाचक की सुविधा का ध्यान रखना एक ओर संपादक की बौद्धिक निपुणता का परिचायक होता है तो दूसरी ओर श्रोता तक वांछित सूचना पहुँचा कर कार्यक्रम की सफलता को भी सुनिश्चित करता है।

रेडियो की तरह टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है परन्तु आज टेलीविजन अपने वैविधथ और संप्रेषण–क्षमता के कारण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। सूचना तकनीक के क्षेत्र में उपग्रह के प्रयोग द्वारा एक अदभुद क्रांति का सूत्रपात हुआ है आज दूरदराज के इलाकों तक भी टीवी की पहुँच है। टेलेविजन के लिए केवल लेखन की कला ही काफी नहीं है वरन दृश्य माध्यम की प्राविधि को ध्यान में रखते हुए कैमरा रिकॉर्डिंग लाइट्स के प्रभाव बीम फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जक्सटापोज फेड–इन फेड–आउट जूम आदि तकनीकी क्रियाओं की जानकारी होनी भी आवश्यक है।

इसी प्रकार मनोरंजन के कार्यक्रमों में सामाजिक राजनैतिक धार्मिक विषयों का जनमानस पर पड़ने वाला प्रभाव इन कार्यक्रमों की भाषा और फिल्मांकन आदि सब का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करना आवश्यक है। अतः सूचनापरक तथा मनोरंजनपरक दोनों ही प्रकार के कार्यक्रमों को संपादन की गहन प्रक्रिया से निकलना पड़ता है। संपादक तकनीकी और भाव तथा विषयवस्तु दोनों दृष्टि से बड़ी बारीकी से सरे कार्यक्रमों को परखता है और पूरे संशोधन एवं परिवर्तन के बाद ही प्रसारण की अनुमति होती है।

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

स्पष्ट है कि कला या तकनीक संपादक के अनुभव उसकी योग्यता बौद्धिकता क्षमता और सूक्ष्म दृष्टि पर आधारित होती है। पत्रकारिता के क्षेत्र की संवेदनशीलता और उसकी विस्तृत पहुँच संपादन के करए की महत्ता एवं गंभीरता में अभिवृद्धि करती है। संपादन का प्रमुख उद्देश्य जनसंचार माध्यमों की पकड़ को मजबूत बनाना तथा जनता तक सही सूचना पहुँचा कर उनकी सत्यता को अक्षुण्ण बनाए रखना है।

संदर्भः

1. संपादन के सिद्धांत – रामचंद्र तिवारी
2. संवाद एवं संपादन कला – प्रो० मधुसूदन त्रिपाठी
3. एडिटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक इरा– मार्टिन एल गिब्सन
4. जे एम सी ३ रिपोर्टिंग राइटिंग एंड एडिटिंग – इंदिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन डिवीजन

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 31102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

SOCIOLOGY OF HEALTH AND MEDICINE IN INDIAN SETTINGS

Dr. D.C Nanjunda
UGC-CSSEIP Research Centre, Mysore University –India
Ph: 09880964840

Abstract: *It is correctly documented that health is not the limited area of medical science, because each and every health culture, irrespective of its ease and difficulty, has its own beliefs and practices connecting to diseases. No culture works in a valueless style in its treatment of diseases. Every culture evolves its own classification and structure of medicine in order to treat diseases in its own way. Even today established contrasts and conflicts exist between the local and the western medical system in Indian rural settings. Experts opined rural India needs medicinal system having the best understanding of social life of the Indian villages. Also it is found that in rural settings doctor and his treatment approach must be suitable to the cultural background of the patient. Introducing any new medical system should be in a position to meet the cultural expectations of the rural patients'. Since the Indian villagers are more conservative in nature emerging medical pluralism needs to focus on social organization and the institutions in the rural settings. This paper is based on the review of various secondary data.*

Background: In Indian society people's concept about health and illness varies from culture to culture, caste to caste, class to class and one geographical area to another. In rural areas the people will normally presume illness may be due to an angry deity or cosmological effects because of sins and crimes committed in the life. Sometime people in the rural parts will connect their health problems due to the sin of their previous life. For example if a person suffering from the blood related problems, sometime people think that person might have killed a holy cow in the lost life. Also sometime rural people think diseases/illness is normally due to the some internal factors i.e. three humors (tri-dosha) of the human body. I e. Air, Bile and Phlegm (vaatha/pittha/ khafa).Sociological studies conducted in many rural parts of the country have generalized that rural people normally classify diseases or illness into two categories, they are

1. An Illness which can be cured by the local healers (folk medicine)

2. An Illness which can be cured only by the western medicine. These classifications will be based on the previous experience of the patient or advice given by the family or village elders from time to time. Car (1955) has conducted some noted studies in rural Rajasthan and narrated about peoples beliefs on health and illness.

In rural India people were really against the western theories of etiology and the curing techniques because of the strong belief in local health culture. Though India is a heterogeneous society, there are certain elements which are common in all types of cultures. This is because of exchange of certain elements over the period of time between the different cultures because of Sanskritisation and Universalisation (Srinvasa,2001). Sociologists have shown how the cultural elements transfer from one society to another. Sometime due to an uneven spread of culture, certain traditions and customs can be seen across the society and sometime only in certain specific geographical areas. This is also applicable to the health culture.

Normally in the Indian rural areas, diagnose of any health disorder will take place initially at the family level. Before visiting the healer people in the rural parts usually practice certain home treatments. The elder people in a particular family will extend their opinion, suggestions and the possible healing treatment for any illness or diseases. Also they will cross-check with other experienced people of the village or friends or relatives through their own social network. In many parts of the rural area, healing approach or theory will be largely decided based on the collective opinion (Tribhuvan, 1988). If the home remedy failed then the patient will visit the local healer/doctors to solve the health problem. In rural areas, we can see some local specialists who are well experienced in curing certain disorders. These local healers use different system of medicines to cure the health problem. Sometime this would be monopolized by some families belonging to the higher caste.

Like economy, religion and politics the health and illness is a part and parcel of the any society. In sociology, the relationship among magic, religion and medicines have been discussed deeply. The Indian sociologists have done in-depth study of the social character of health and sickness. Truly speaking the field of medicine comprises a number of individuals interacting with each other influenced by the local health culture and the society. In this way the concept of health, illness and medicine will be largely influenced by the particular type of culture mainly. Hence

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

health and illness should be studied in a holistic way from the lens of the socio-cultural factors. Each and every individual will develop the health seeking behavior or health care seeking behavior over the period of time. Sometime the health seeking behavior may be similar or different. In this background the Indian sociologists have tried to study the social dimension of health and illness and response of the Indian society.

Certain studies conducted in the Indian rural parts have provided some valuable notion about the illness ideology of the Indian rural folk. Sometime illness will be handled in a non-magical and non-religious way because diagnosing and the curing of the various illness differs from culture to culture. People would believe the shamans or priests only can interpreter the supernatural phenomena causing health issues. Sometime rationale for choosing a particular type of treatment/healer will be based on the suggestions given by some other people who were a victim for the same problem. Also they guide the suitable healer, he/she had approached previously to cure that health problem. Thus the patient‘s perceptions about the origin and cause of illness and healing take its meaningful course towards the specific healer in a given situation in rural parts. Shaman‘s ideology is that whatever illness causes due to the spiritual reason, should be handled in spiritually way only. After conducting many diagnostic rituals, healer always administer medicines to their patients‘to make healing meaningful and to rise the comfort level of the patient at best (Basen,1992; Chopra, 1984).

There are two major division of curing techniques in traditional Indian medicine system;

1. One who diagnose and use appropriate theory based on the magical power or supernatural power
2. One who respects and honors the patients’ self-diagnosis and suggests suitable therapeutic measures.

It is found that entire set of ritual performances including the chants, songs; pooja, gestures, etc. have a lot of underlying scientific meanings. Only the healers would know about these meanings and can interpret these meanings. Whatever meanings involve in a healing procedure is embedded in a symbolic system and it represents the cultural order of that community in a given geographical area. Whatever ritual performance takes place with preventive, curative and pro motive for the betterment of the health status in any cultural settings will be normally and clinically meaningful reality. The main aim behind any ritual performance and healing

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

techniques would be to identify the origin, and the reasons for the health disorder. Further, the rituals would be conducted to honor or to compromise with cosmic powers or spirits or pathogenic agents to restore the disturbed cultural order. Since people perceive illness is an indication of impurity of mind and soul, people would think mind and soul should get purified through the various ritual healings (Stacey, 1988).

Chaudhuri (2012) write about Indian medical sociology writes: It is rightly recognized that health is not the restricted sphere of medical science, because each and every health culture, irrespective of its simplicity and complexity, has its own beliefs and practices relating to diseases. No culture works in a worthless fashion in its treatment of diseases. Every culture evolves its own classification and structure of medicine in order to treat diseases in its own way. Thus, treatment of the disease may differ among various social groups. To comprehend the health and health-related problems in an accurate viewpoint, it is extremely significant to think about the socio-cultural factors surrounding the health issues. This is an extra relevant factor in the rural areas too. Studies conducted on sociology of health and illness in India has used an existing social structure as the basic unit for the reference. Caste and class will play specific roles and in rural areas some time people belonging to the higher caste will be the power centric and even they can control the money and health. Even though the western medical system has an edge over the traditional one, its success depends on how good it gets a reliable space ―between the realm of outsider and the inner realm of kinship (Morriot,1955; Kakar,1990).

Caste and religion have close similar/dissimilar associations in using specific/different kind of medical system in rural settings. Also few studies have shown religion has no connection with using a specific type of medicinal system. Sujatha (2003) in her study has opined usage of Unani system is quite universal in Kerala, while people belongs to another religion in UP & other states are sparingly use Unani in all walks oflife. Sidda system is relatively rare among the Muslims and Christens‘where it is quite common in case of low caste Hindus especially among the tribal people (Kakar,1990). Faith healing is a common phenomenon with the Hindu‘s and Muslims and it is most uncommon among the Christens. Hence it raises some important question regarding the relationship between different religious background and the usages of a specific type of medicine available in the society. Ayurvedic is an oldest system of medicine in our society and it is more prevalent among all the religion. Uberoi (2002) has opined in some part of the world people

would like to differentiate between religion and the medicine based on the procedures involved in curing sessions. Otherwise any identification of any type of medical system would lead to the communal issue (Sujatha, 2002).Burton (2008) has opined that the relationship between the caste and medicine especially in the postindustrial society is a significant sociological issue. Certain castes in rural areas have dominated on the traditional medicines. It has become a family business today. Also it is found that certain traditional healers would like to extend the treatment. Only for the patients'belonging to his/her caste only. Sujatha (2003) felt in British regime traditional medicinal system was an important tool for the caste mobilization. Abraham (2010) felt caste comparison and caste based treatment have been plagued in the traditional medicine system in the rural parts of the country today. It is also found, because of the caste and class conflicts and the medicalizations, the socially excluded communities are suffering a lot in the rural parts of the country.

Sociologists from the long back are showing interest in studying various segmentation of the society and emerging medicinal system. Also the sociologists are doing some comparative studies about the medical pluralism using by the various castes and ethnicity people as a strong indicator/parameter in evaluating the heath inequalities in rural aprts. Sujatha (2005) has found each and every caste in India has its own health culture, tradition, ritual, diet in a given society**.** Also it is noted in a multi caste society the health culture and health seeking behaviors varies significantly under the changing social system due to the various external factors. The lower caste people mostly prefer only the traditional medical care for any health problems while the higher caste people will opt the quality medicines. There economic conditions also play a vital role too.

In rural areas each and every caste has its own healer some time the caste factor of a local healer would be a significant issue too. The caste based medical skills also an important issue for the debate today. Though the female traditional healers available in the every society, they are not getting enough importance. Lee and Bery (2005) have opined 'religious/caste based offers will play a vital role in meaning positive and mental health in the area of onset of a disease, cure and general well-being'. Next, Raghulam et. al, (2002) and Razali et. al, (2002) have opined 'some religion and caste based health practices will be used as both the psycho-biological and cultural healing practices'. Further Winkelman (2002); West (2000); Koching and Comen(2002) and

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

Seligner (2005) have opined some healing practice‘s taking place in religious places like Masque‘s, (dargahs) and the Churches‘ will be a type of recovery oriented approach to come out of the mental trauma in India. Also Statsny and Lehmann (2007) and Minkowitrz and Dhanda (2006) have opined that religious practices for healing will help the patients‘ to come out of his/her illness and guide others to recovery as soon as possible. Hence the caste and religion have a very close association with health and illness issue in rural areas.

Medical Knowledge and Power

Crinson (2007) writes

‘Power is essentially relational rather than something that is possessed by individual doctors or the medical profession as a part of social group’

As we know the Development of the medical knowledge has a long history. The Bio-medical science helps us to reveal the cause and effect with special reference to the health and illness issue. The scientific understanding health and illness can only be applied through the material practice. The Medical knowledge evolved as an organizational system of formal health care system in this globe. This formal health care system through the material practice has become socially embedded gradually. The Medical knowledge, education and power are the core part of the modern health care system (Crinson, 2007). Earlier, experts were used to define the term medical knowledge as Medical Cosmologies‘.

This it shows the medicine has a close relationship with the society or it is a part and parcel of the society. The evolution of medical knowledge has its own root within the societal domain. The medical knowledge composed of both the science and social sphere. Before industrialization, the doctors were used to judge the sick person based on the personal attributes of the patients‘. Institutional (hospital) based medicinal system has developed in association with the continuing phase of the social change. The Medical knowledge evolved along with the industrialization, urbanization, capitalist society etc. Along with this, the doctor- patient balance of power begun to change. The Medical knowledge has gradually started to pass from the patient to the doctors.

New medical discoveries and the improvised treatment started to emerge. Foucault (1973) coins the term―Clinical Gaze for this. Also he showed the importance of the social relationship of the medical knowledge between the physicians‘and patients‘. Power is a kind of an approach or

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

discursive practice which is the core part of an emerging social system. Power exists at all the levels which controls the different segments of the society including the health.

In the case of medicine, power is nothing but scientific knowledge associated with modern medical health care systems including hospitals, physicians, medicines etc. Since any health care system needs to work within the society this often referred as biomedical discourses. Power and knowledge are the most vital for both development of new health care system and its sustainability in the society. Armstrong‘s (1983), opines ―'any new health policies, schemes or progrmmes are just a kind of medical power channelizing through the supervision of a communities health seeking behavior'. Further, Crinson (2007) has felt all health polices basically would have some vested interests. Hence, sociologists felt this is the time to negotiate with the medical knowledge and power for maximizing health status of a layman.

Bhasin (2006) has opined underestimating the traditional medical system may not promote the biomedical therapy in rural areas all of a sudden in India. We cannot just overlook the efficacy of the traditional medicine just because of it is being used by the people over the centuries. Rapid expansion and promotion of the medical system and knowledge could not affect the popularity and avoid in using the traditional medicine. She opined experts should work on reducing the complexities and problems involved in using the biomedical system. Normally rural folk does not want any new medicinal system to been encroached into their traditional health culture. Any new medical system should commensurate with their socio- cultural systems. We must have an understanding of diverse culture and the traditions in the current medicinal system and health culture.

Medicalization: It is nothing but an expansion of the medical jurisdiction in the areas normally thought non-medical (Szasz, 2007). Defining the term medicalisation is quite complex because we cannot clearly separate the medical issue from the non-medical domain focusing the societal perspective. Because there are so many factors which effecting separately on both the medical and non-medical domains including the power, knowledge, professional objectives, political economy, socio-cultural issues, patients‘ interest etc. Illich (1976) has opined day by day more and more segmentation of human life has been brought into the bio-medical influence‘. The concept of medicalisation reflects both interactions and the Marxist approach focusing health and illness. It is an extended part of the social domain of medicine. It is opined that the

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

medicalization has undermined the people's ability to take care of their own health and medicalisation has a dual role to play like;

1.It discloses and eradicates the diseases 2. It negotiates the diseases into sickness. Parson (1964) has opined establishing what is medical and non-medical will be the base for the medicalisation and is the result of the functional connection between curing the diseases and the normal functions performed by the sick role. Sickness according to Person is a social fact between physician and the patient corresponding to their wider social roles'(Parson, 1964).

Zola (1978) has opined that the medicine acts as a tool to control the society and medicine is a vital agency or force in medical zing society'. Medicine has become legitimate control over the people's health. Sometime the medicine expands its influence unnecessarily even on the healthier individuals too. Friedson (1998) opines political aspects acts as a powerful process in the society taking forward the expansion of medicalization process rapidly'. Kennedy and Kennedy (2010) opined social construction is the core part to reveal the role of medicine in the medicalization of the society. The social construction process moves through a sociological frame of reference naturally. Indirectly, sociological components of the medicine will play a vital role in the various stages of the social constructions of medicalization.

Conclusion: Today the medicalization has expanded to cover bio-technology, consumers and the insurance sector also. At present the commercial domain of medicine is fast expanding. Now a day's every human problem in being considered as a medical problem and are trying to solve it medically only. Sociologists are now focusing on how a disease normally develops, considers medically valid and treat the patients'accordingly. Some of the natural phenomena which are common in the human life are also being labeled as medically valid for some type of treatment! Sometime problems among the human relations will also be treated medially! Also complicated social problems are being treated medically today! It seems that it has become a tradition human problems are being treated scientifically rather than addressing the real underlying socio-culture or other cause for the actual problem (Pieris, 1999). On the other hand, it is found that the medicalization play a vital role in providing an advanced and the scientific health care system. Some Sociologists have opined some time the false lay knowledge about the illness/disease may decrease the relationship between the Doctors and the patients'and there by the medicalization

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

expands in the society rapidly. The process of medicalization is of vital issue to be debated in the new health care sector focusing the rural folks.

References:

1. Armstrong‘s (1983) Disease, Treatment and Health, Oxford: Oxford University Press
2. Bhasin(2006) The Unani Traditional Medical System in India: A Case Study in Health Behaviour, Anthropologist 7(2).
3. Chaudhuri, B, Social Science, health and culture : The Tribal Situation. Social Action, 39:243-253 (1986).
4. Crinson(2007), Studies in Pharmaceutical Anthropology, Kluwer: Academic Publishers
5. Chopra (1984) People‘s Perception About Child Hood Illness And Their Therapeutic Practices And Preferences In Four Selected Villages Of Raipur Rani Block,
6. Comen(2002)
7. Pieris, Indrani (1999), Disease, Treatment and Health Behaviour in Sri Lanka, Oxford University Press
8. Illich (1976) Post Human. Amsterdam: Idea Books.
9. Kennedy (2009) Power, Knowledge, and Medicine: London: Routledge.
10. Koching and Comen (2002), The Body and Society (2nd Edt.). London: Sage.
11. Kakar, (1990) Anthropology in medicine A Review in P C Joshi. A. Mahajan (Edt) In Medical Anthropology, Reliance Publications, New Delhi.
12. Payyappallimana (2011) Traditional Medicine in Health System Development: A Case Study of Kerala State, India, Yokohama Journal of Social Sciences, Vol.15, No.3, 77-101
13. Srinivasa(2001). An analysis of primary health care administration in Karnataka Punjab University Journal. 12(6):24-28.
14. Stacey, M. (1988) The Sociology of Health and Healing, London: Routledge.
15. Seligner (2005) Social Anthropology and Medicine, Academic Press, London.
16. Sujatha (eds), Indigenous Medicine, State and Society: Medical Pluralism in Contemporary India. New Delhi: Orient Blackswan.
17. Winkleman, (2002) Consumers in Health Care: Beyond the supermarket model, Policy and Politics, 15 11: 1-8.
18. West (2000) cultural factors in spatial organizations in culture and experience. Philadelphia, University of Pennysylvania press.
19. Thribhuwan, (1998) Medical world of the Tribal’s, : New Delhi: Discovery Publications.
20. Winkelman (2002); Health culture and community case studies of public reactions to health. Programmes. Newyork : Russel sage Foundation.
21. Zola, I.K (1978) Medicine as an institution of social control: The Medicalizing of Society, In D.Tuckelt And J.M Kaufert (Eds) Basic Readings in Medical Sociology London: Tavistock Publications.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 32102017
Peer–Review Refereed Research Journal

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

ERA OF DIGITAL INCLUSION-
AN EXPLORATORY STUDY OF INDIAN E-MARKET

Saroj Bala Dewatwal, Assistant Professor,
Department of EAFM,
University of Rajasthan, Jaipur

Abstract: *The catalytic push in demonetized India has taken us towards digital era. In aftermath of demonetization economy is encouraged for digital payments system. E-banking, mobile banking, usage of plastic money with alternative modes such as virtual wallets / E wallets & apps have captured the market. These initiatives assisted in smooth transition towards digitalization. This drive has promoted the flagship scheme of Government of India to transform India into a cashless and knowledge economy. It has provided an opportunity for digital inclusion in India. The present paper explores the opportunity for being cashless and creation of digital identity. A study of E-market has been done to highlight the opportunities for growth in India and to be a part of digital revolution. This endeavor must also be accompanied by an awareness programme to educate & motivate general public to use e-payment options. Digital literacy is promoted in India in addition to other initiatives.*

Keywords - Digital identity, cashless economy, demonetization, m-wallets and technology.

Introduction and Literature review

The demonetization drive has accelerated rapid growth in the electronic payments system in India. Usage of e-banking, mobile banking, plastic money, virtual wallets/ e wallets & digital apps has increased in the economy. The commonly used apps in India include PayTm, Ola money, Mobikwik, Google Wallet, Pay U Money, State Bank Buddy, ICICI Pockets, HDFC Chillr etc. Besides these UPI solutions, Ru-pay, Aadhaar Pay and BHIM app are also

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

contributing in smooth transition towards digital inclusion. Digitalization can further be promoted by boosting e-commerce transactions. The government's vision of digital India has motivated the digital service providers in India to operate a campaign to attract new customers. The drive has provided an opportunity to use technology. The data in the present paper has been collected from secondary sources. It includes reports of Department of Electronics & Information Technology (DeitY), RBI bulletins & newsletters and websites of banks concerned. Report of RNCOS business consultancy service firm is used for forecasts and potential study.

Objectives of the Study

- To study the E- market potential in India
- To analyze the challenges of digital economy
- To search new opportunities for digital inclusion

Movement towards Cashless Economy

Cashless economy uses digital mode for transactions and replacement/ decline in cash transactions. In it, electronic channels are used as modes of transaction. The digital payment system includes electronic avenues and digital apps by National Payments Corporation of India. After demonetization the digital payment system has gained momentum.

Growth in digital modes of payments (in Post demonetization period)

Mode of Payment	(Value in Rs. Billion)			Change (%)	
	Decembe, 16	January, 17	February, 17	Feb 2017 over Nov 2016	Feb 2016 over Nov 2015
NEFT	11538	11355	10878	23.5	14.3
CTS	6812	6618	5994	10.6	19.2
IMPS	432	491	482	48.5	23.2
UPI	7.0	16.6	19.0	2001.2	-
USSD	0.104	0.382	0.357	4789.4	-
Debit and credit cards at POS#	522	481	391	11.1	-5.6
PPI *	21	21	19	41.9	15.2

Mode of Payment	(Volume in Million)			Change (%)	
	December ,16	January, 17	February, 17	**Feb 2017 over Nov 2016**	**Feb 2016 over Nov 2015**
NEFT	166	164	148	20.4	10.4
CTS	130	118	100	15.3	18.0
IMPS	53	62	60	65.2	25.1
UPI	2.0	4.2	4.2	1346.1	-
USSD	0.102	0.314	0.225	3091.9	-
Debit and credit cards at POS#	311	266	212	3.3	3.9
PPI *	88	87	78	32.8	4.3

Source- RBI Collected and compiled according to available data, includes other charges, exp. also

- : Comparative data not available # card transactions of 4 banks

PPI * -Postpaid Payment Instruments issued by 8 non bank issuers

Note (abbreviations): NEFT (National electronic funds transfer)

CTS (Cheque Truncation System)

IMPS (Immediate Payment Service)

UPI (Unified Payments Interface)

USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

Mobile Wallet market in India: Mobile wallet is a very useful application for transferring money in both urban & rural areas even without using a bank account. Mobile wallet users enjoy greater flexibility in making secure payments. Also, those who do not possess credit or debit cards can go to their nearest wallet recharge kiosk and get their wallets loaded against cash. Thus, mobile wallets play a vital role in digital inclusion and moving towards cashless economy in India.

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 32102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

There are four types of mobile wallets available in India:

Open Wallet- It is the one that allows a user to buy goods and services, withdraw cash at ATMs or banks and transfer funds. These services can only be jointly launched with a bank. Additionally, it allows its users to send money to any mobile number bank account. One example is M-Pesa by Vodafone and ICICI.

Semi-open Wallet – It is the one that allows its users to transact with merchants that have a contract with the semi wallet company. A user cannot withdraw cash or get it back, he will have to spend the amount he had loaded. One common example is Airtel Money.

Closed Wallet - It is quite popular with e-commerce companies. Here, a certain amount of money is locked with the merchant in case of a cancellation or return of the order or gift cards. Example: Flip kart e-wallet

Semi-Closed Wallet - It does not permit cash withdrawal or redemption but allows users to buy goods and services at the listed merchants. Example- Paytm

Types of prepaid instruments (M-Wallet)

Type	Closed PPI	Semi-closed PPI	Semi-opened PPI	Open PPI
Entries allowed to operate	Banks, NBFC, other entities	Banks, NBFC, other entities	Only Banks	Only Banks
Requirement of KYC	No	Not mandatory	Yes	Yes
Maximum Amount that can be stored in PPI by card holder	INR10000	INR 10,000 (without KYC) INR 50,000 (with KYC)	INR 1,00,000	INR 1,00,000
Examples	Life style gift card, Metro	Oxigen, Paytm, Mobikwik, etc.	Gift cards by Axis bank, Food card	Vodafone M-pesa

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

	Card, Flipkart Wallet, etc.		issued by HDFC Bank, etc.	

Working of M-wallet

Smart phone Users can install m-wallet application on their mobile phone
M-wallet owners can create their log in account
Receipt of PIN by the User
Availability of options- Money to Banks, friends, Merchant Payment, Recharge, and Bill Payment
A Bank account holder can load his m-wallet through net banking, debit card, credit card or cash
A Non-Bank account holder can load his m-wallet through visiting any m-wallet store
After loading of Cash, the user can make payments.

Revenue Generation Mechanism of M-wallet Companies

- Commission income from the sale of recharges- The companies facilitate recharge of talk time, utility bill payments and earn commission for these services.
- Commission income from merchants- This income is recognized when the services are rendered to the merchants of the company with respect to the value of transactions done by users of the company's wallet on the respective merchant's website.
- Onetime Setup Fees from Merchants- This income is recognized when the services are rendered to the merchants of the company with respect to registration of the merchants' on company website.
- Interest Income- This income is recognized on accrual basis on a time proportion basis at the applicable rates of interest.
- Income from forfeiture of unused users' Wallet Balance- This income is recognized when the user amount is forfeited.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 32102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

Revenue Generation Model of M-wallet Companies in India

→

M-Wallet Companies

- Airtel Money
- Vodaphone M-Pesa
- Idea Money
- Oxygen wallet
- Paytm
- Mobikwik

dings

Tie-Ups

Receives certain percentage as commission on every transaction

Maj or Fin

M-Wallet User:

Banks

Movies

Airlines

Utility bills

others

Revenue generation to M-wallet companies

A study of m-wallet market in India is done to study demonetization impact on digital payments growth. Secondary data has been used to forecast the potential. This research has been conducted by a business consultancy service firm, RNCOS regarding transactions being done through m-wallet. The data of 2016 has been taken from the reports of RBI. The m-wallet transaction's volume, value and market share is presented. Estimate for 2017 and forecasts from 2018 to 2022 has been made for the m-wallet transactions for promoting digital payments in India and progressing towards cashless economy.

Transaction Volume of M-wallet (billion), FY 2016 to 2022- In the year 2016, total m-wallet transactions were 0.6 billion and it is expected to reach 260 billion by FY 2022, growing at a CAGR of 163%.

Transaction Value of M-wallet (billion), FY 2016 to 2022- The mobile wallet transactions in India have grown about 20 times to reach INR 206 billion in the year 2016 from INR 10 billion in the year 2013. Mobile wallet is one of the fastest growing paperless mode of payment and it is expected that the majority of transactions will go paperless in near future. It is also forecasted that the market value of m-wallet transactions in India will grow at a CAGR of 211% to reach INR 275 trillion in the FY 2022.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

M-wallet Market Share (INR billion)), FY 2016 to 2022- The Indian m-wallet market in the year 2016 was around INR 1.5 billion and it is forecasted to grow at a CAGR of 196% to reach INR 1512.5 billion in the year 2022.

Mobile Payments in India

M-payment is a crucial driver for growth of E-commerce industry in India. It is transfer of funds by credit cards or debit cards. The common examples are online fund transfers, booking of movie tickets, rail tickets and payment of utility bills.

Transaction Volume of Mobile Payments (billion), FY 2016 to 2022- During FY 2016 the total transaction volume of the m-payment in India was 2.9 Billion and it is expected to reach 460 billion by FY 2022, growing at a CAGR of 132%.

Transaction Value of Mobile Payments (trillion), FY 2016 to 2022- In FY 2016 Indian m-payment was reported 8.2 Trillion in transaction value and it is expected to reach 2205 Trillion by FY 2022, growing at a CAGR of 150%.

Major challenges ahead

- Lack of digital infrastructure
- Lack of potential users/ willingness
- Lack of high speed internet
- cyber insecurity
- lack of digital literacy

Search for new opportunities

The demonetization drive has pushed us towards digitalization. However efforts are still needed to promote digital payments. It includes removal of roadblocks in penetration of payment technology. Initiatives to educate and encourage people by both government and private sector are needed. Digital inclusion will reduce the cost of cash handling and will increase accountability, tractability and tax compliance in India.

Suggestions and future scope

A unique digital identity is urgently required for development of virtual economy in addition to better digital infrastructure and cyber security mechanism. Other steps include changing the mindset of Indians and encouragement towards adoption of digital platform. To sum up, vast opportunities are available for digital inclusion in demonetized India.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

References

1. Official report/ Department of Electronics & Information Technology/ Ministry of ICT/ Govt. of India /2015/digital India
2. Report of RBI/2017/ Macro-economic impact/Govt. of India
3. Annual resource guide/ 2016/Banking and Finance
4. Manual/ M-wallets/2016/ the Associated Chambers of Commerce and Industry of India/report/New Delhi/ India/ RNCOS
5. Official report of World Economic Forum//2016/world bank group
6. Nascom/ annual report/2016-17/ digitizing india /annual.
7. Official websites of concerned banks.
8. www. niti.gov.in.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 33102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

देश के विकास में सहायक सामुदायिक रेडियो स्टेशन

डा. सुरेंद्र, असिस्टैंट प्रोफेसर,

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़

कपिल भाटिया, असिस्टैंट प्रोफेसर,

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़

मुख्य शब्द– प्राकृतिक आपदा, अन्ना रेडियो स्टेशन, महिला सशक्तिकरण

अगर हम यह कहे कि जनसंचार के इतिहास में रेडियो एक अदभूत खोज है तो हम गलत नहीं है। विश्व में पहली बार कम्यूनिटी रेडियो सन 1982 में अफ्रीका में तथा सन 1986 में एशिया महाद्धीप में आरंभ हुआ। अगर हम विश्व में कम्यूनिटी रेडियो की तेजी की बात करे तो यूनेस्को ने सन 1997 में अपनी एक रिपोर्ट वर्ल्ड कम्यूनिकेशन जारी की और इसके माध्यम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर जोर दिया। क्योंकि यूनेस्को को यह लगता था कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन दबे कुचलो की आवाज है और यह विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इसके साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन पिछड़ो को विकास में भागीदार बना सकता है और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी कर सकता है तथा लुप्त होती संस्कृति को बनाये रख सकता है और लोगों को सीधे जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है। इसके साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर कोई भी अपना कार्यक्रम दे सकता है और इस पर खर्च भी बहुत

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 33102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

कम आता है और इसके लिये बहुत ज्यादा गुणवता की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिये आज विश्व के 100 से ज्यादा देशों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन कार्य कर रहे है।

इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि जब महात्मा गांधी जी पहली तथा अंतिम बार आकाशवाणी रेडियो स्टेशन पर 12 नवंबर 1947 को गये तो उन्होंने रेडियो के बारे में कहा कि यह एक अदभूत शक्ति है और मैं इसको देख रहा हूं तथा यह भगवान का आर्शीवाद है। उनको लगता था कि रेडियो है वह भारत जैसे पिछड़े देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ा सकता है।

रेडियो स्टेशन स्थापित करने की बात तथा इसे विकास में सहायक बनाने की बात में महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब 1995 में सुप्रीम कोर्ट के जज सावंत जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहा कि जो वायु तरंगें है वह जनता की संपति है और इनका प्रयोग जनता के विकास के लिये होना चाहिये। इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि सरकार ने भी इस आदेश के आने के बाद रेडियो का विकास करने के लिये एक खाका तैयार किया और सन 2002 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिये एक नीति तैयार की।

इस नीति के तहत सरकार ने सबसे पहले शिक्षा संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोलने के लिये आमंत्रित किया। तथा सामुदायिक रेडियो के लिये 87.5 से लेकर 108 मैगाहर्टज तक की फ्रीक्वेंसी सामुदायिक रेडियो के लिये आवंटित की। इसी नीति के तहत1 फरवरी 2004 में देश में पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अन्ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन तमिलनायडू में आरंभ हुआ।

इसके साथ ही सरकार ने 16 नवंबर 2006 की नीति के तहत सिविल सोसायटी तथा एनजीओ को भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन आरंभ करने की अनुमति प्रदान की तथा 100 वाट का ट्रांसमीटर तथा 30 मीटर उंचाई तक एंटीना लगाने की अनुमति प्रदान की। सामुदायिक रेडियो स्टेशन न केवल समय की आवश्यकता है वरन यह विकास में भी बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभा सकता है।

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

अगर हम आज के समय की बात करे तो देश में लगभग 400 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तथा सबसे ज्यादा रेडियो स्टेशन तमिलनायडू राज्य में है। इसमें भी महत्वपूर्ण है कि भारत में लगभग 300 रेडियो स्टेशन तो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से चलाये जा रहे है।

इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि जनवरी 2017 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया और कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन आकाशवाणी के समाचारों का हूबहू प्रसारण कर सकते है। लेकिन प्रसारण करते हुए उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रसारण में किसी प्रकार का संशोधन, संपादन या विश्लेषण नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि वो सूचना के नाम पर मौसम की सूचना का प्रसारण तथा यातायात का हाल बता सकते है। जो कि लोगों के लिये विकास में कही न कही सहायक होगा।

विकास में सहायक

सामुदायिक रेडियो है वह विकास में भी सहायक है क्योंकि सामुदायिक रेडियो चलाने के लिये जो नियम कायदे है उसमें साफ तथा स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें 50 प्रतिशत क्षेत्रीय भागीदारी आवश्यक है। इसके साथ ही रेडियो स्टेशन पर जो भी सामग्री जाएगी उसको 90 दिन तक सुरक्षित रखना आवश्यक है। इससे सरकार है जब चाहे उस रेडियो स्टेशन को देख सकती है और पता कर सकती है कि नियम कायदों में कही ढिलाई तो नहीं बरती जा रही है। इसके साथ ही सामुदायिक रेडियो को शिक्षा, स्वास्थ्य व संस्कृति से सम्बंधित कार्यक्रम बनाने होते है तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल करना होता है।

महिला विकास में सहायक

ये रेडियो स्टेशन न केवल महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते है वरन बताते है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से सम्बंधित सरकार की कौनसी योजनायें है और इन योजनाओं का महिलायें किस तरह से फायदा उठा सकती है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन महिलाओं को पौष्टिक आहार तथा

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

गर्भधारण जैसे विषयों में भी जागरूक करते है। इसके साथ ही सामुदायिक रेडियो स्टेशन महिलाओं को कानूनी अधिकारों तथा संपति के अधिकारों व शिक्षा के प्रति भी जागरूक करते है।

किसानों को जागरूक करने में सहायक

सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को मौसम की जानकारी देने में तथा फसलों तथा बीजों की जानकारी देने में तथा किस प्रकार से सही फसल उत्पादन करे इस प्रकार की जानकारी देने में भी काफी हद तक सहायक है। इसके साथ ही ये रेडियो स्टेशन यह भी बताते है कि उनको कहां से सस्ती दरों पर कृषि के लिये लोन मिल सकता है और उस प्रकार किस प्रकार की सब्सिडी मिलेगी। किसान किस प्रकार के खाद तथा कीटनाशकों आदि का प्रयोग करे और किस तरह से फसल की सिंचाई करे।

शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार में सहायक

सामुदायिक रेडियो स्टेशन शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार में सहायक है। रेडियो स्टेशन यह बताते है कि किस विश्वविद्यालय में किस प्रकार के कोर्स इस समय चल रहे है और किस विषय में प्रवेश के लिये क्या योग्यता है और कैसे हम किसी विषय में प्रवेश ले सकते है। इसके साथ ही इस कोर्स को करने के बाद क्या अवसर है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन इसके साथ ही यह बताने में भी सहायक है कि किसी विषय मे अगर कोई छात्रवृत्ति है तो वह किस के लिये है और इसके लिये क्या योग्यता है।

संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार में सहायक

आज प्राय छोटी संस्कृतियां लुप्त हो रही है और बड़ी संस्कृतियां उनको अपने अंदर समेट रही है। लेकिन हम सामुदायिक रेडियो के माध्यम से न केवल छोटी संस्कृतियों का प्रचार तथा प्रसार कर सकते है वरन उनको बनाये भी रख सकते है। इसके साथ ही सामुदायिक रेडियो छुपी प्रतिभाओं

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

को एक मंच भी प्रदान करता है। जिससे उनको आगे जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार से सामुदायिक रेडियो स्टेशन लोगों को आगे बढ़ाने के लिये एक प्लेटफार्म का भी काम करता है।

प्राकृतिक आपदा में सूचना पहुंचाने में सहायक

प्राय रेडियो के माध्यम से हम तेजी से तथा तुरंत सूचना भेज सकते है। अगर हम भारत की बात करे तो देश में हर समय कही न कही प्राकृतिक आपदा हर समय तैयार रहती है या उसका माहौल बना होता है। प्राकृतिक आपदा के समय जान तथा माल की रक्षा करना अति आवश्यक है। यह सभी संभव हो सकता है तुरंत सूचना पहुंचाकर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन इस मामले में मिल का पत्थर सिद्ध हो सकता है। अगर हम देखे तो जापान में प्राय इस प्रकार की प्राकृतिक आपदायें आती रहती है और वहां पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहे है। इस प्रकार का ही कार्य ये रेडियो स्टेशन यहां पर भी कर सकते है।

रोजगार सम्बंधी सूचना देने में– सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्षेत्रीय लोगों को रोजगार सम्बंधित सूचना देने में तथा उसके लिये क्या योग्यता है और किस प्रकार की सुविधायें मिलेगी। इस प्रकार की जानकारी देने में सामुदायिक रेडियो स्टेशन अति आवश्यक है। क्योंकि ग्रामीण तथा पिछड़े लोगों की अन्य माध्यमों तक इस प्रकार की पहुंच नहीं होती है जिस प्रकार की रेडियो पर होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Community Radio Policy document (2004) , (2006),(2016)http://www.mib.nic.in/writereaddata/html_en_files/crs/CRBGUIDELINES041206.pdf last accessed on 29 nov 2016.
2. Fraser, C. and Estrada, S.(2001) Community Radio Handbook. Routledge Paris: UNESCO
3. Rogers, E. M., & Kincaid, D. L. (2007). Communication networks: A new paradigm for research. New York: Free Press.
4. Fleck, J. (1988). Innofusion or diffusation? The nature of technological, Routledge Paris.. Community Broadcasting Association of Australia. Retrieved 5 May 2012.
5. ACMA—Community broadcasting Archived 2013-05-09 at the Wayback Machine.
6. ACMA—Licence allocations, renewals and transfers Archived 2013-04-13 at the Wayback Machine.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

7. The National Campus and Community Radio Association
8. Campus and community radio policy
9. Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Community Radio Stations Archived 2007-11-16 at the Canadian Government Web Archive
10. Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications
11. Indian Ministry of Broadcasting—Community Radio Stations
12. http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Community-radio-protests-against-spectrum-fee-hike/articleshow/13101664.cms
13. Community radio gets Rs 100 Crores in Budget 2014-15". IANS. news.biharprabha.com. Retrieved 10 July 2014.
14. "FM of the Masses". Retrieved 22 April 2013. |first1= missing |last1= in Authors list (help)

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 34102017
Peer–Review Refereed Research Journal

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

URBAN HOUSING: ISSUES IN INDIA

Vishakha Sharma, Research Scholar,
Chaudhary Ranbir Singh University, Jind (Haryana)

Key Words: Growth. Progress. Prosperity.

Introduction: And more awaits those who are going to be a part of the rapid urbanisation of India. However, urban India is divided into two halves. One is the prosperous half which conforms to high global standards while the other one is plagued with poverty and abominable living conditions. Cities and towns are emerging as centres of economic growth as they contribute significantly to the economy and economic opportunities. This has led to migration and an increase in the rate of urbanization. Delhi, for instance, has recorded an increase in population density from 11,000 people per square kilometres in 2011 to around 19,000 people per square kilometres in 2014. Nearly 28% of the country's population lives in cities and urban areas, and this is expected to rise to 40% by 2020. This growth in population is not accompanied by a similar growth in infrastructure, especially housing. Therefore, the people who come to the city seeking a better life are left with a one which is worse in several aspects.

The biggest challenge for people living in slums is housing. Living in tinned, single-roomed houses for a whole family is a big challenge, just as lack of toilets and shower blocks, lack of clean water.

I feel that there is potential for inclusive growth in the urbanisation of India and the first step towards that should be with affordable housing in mind as it affects the overall standard of living of the people. Vulnerability of those without shelter and sanitation facilities is a detriment to the progressive outlook a city is built on. Plus there are far-reaching repercussions of a capacity-deprived labor force living in poor conditions. There is a need to understand the challenges the government and the people face with housing. The study helps us get a picture of what has gone wrong and what steps we can take to fix it.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

Literature Review: India has been growing, and in the process has provided its citizens with a myriad of opportunities to include them in its growth. And thus we see a large influx of people from surrounding areas into towns and cities which are the hubs for these prospects. The rate of urbanisation over the past 5 decades has ranged between 2.7% to 3.8%. In 2001, 68.7% of 286.1 million of India's urban population lived in class I cities, i.e. the cities that have a population of over 0.1 million.

However, there are various fallouts due to which we have failed to accommodate people in the city, especially from the lower segment of the society. There has been fallout in terms of proliferation of slums, high prices of land and building materials which render houses unaffordable.

The census of 2011 estimated a 65 million slum population in 4041 statutory towns. The Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation set up a technical committee which estimated a shortage of 18.78 million housing units during the 12th Five Year Plan period. From these 18.78 million units 95% of the shortage is estimated in the Economically Weaker Sections (EWS) and the Low Income Group (LIG) categories.

Housing is considered affordable if a basic housing unit that provides a minimum amount of personal space and basic amenities is accessible at 20%-40% of the gross monthly household income for either rent or mortgage. Even though the National Urban Housing & Habitat Policy of 2007 as well as the 11th Five Year Plan remains silent on an official definition of EWS & LIG housing the definition that prevails happens to be minimum 250 square feet for EWS and minimum 300 square feet to 325 square feet for LIG.

Urban Housing Scenario:

Housing Shortage in Urban India

	Monthly Per Capita Expenditure	Estimated Number of Households (2007)*	Housing Shortage in million (2007)	Percentage Shortage
EWS	0 - 3,300	21.81	21.78	99.9%
LIG	3,301 - 7,300	27.57	2.89	10.5%

Source: Report of the Technical Group (11th Five Year Plan: 2007-12) on Estimation of Urban Housing Shortage

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 34102017
Peer–Review Refereed Research Journal

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

The Indian urban centres are in the midst of an affordable housing crisis. The gap between the supply and demand of the housing has been widening thus pushing up the market rates for housing making it harder for the poor to afford housing. The lack of availability of housing and basic services at a pace required to meet the challenges of urbanization has resulted in the development of slums and squatter settlements with wider ramifications on the health, safety and well-being of the citizens. In 2001 it was recorded that about 2.3% of the households had no exclusive rooms and 35% lived in one room houses. Even the quality of housing was deplorable with about 8.08 million houses being ‘semi-pucca’ and 2.7 million being ‘kutcha’.

The inability of the private sector to jump in has pushed the government deeper into trouble. Private sectors continue to push projects for more luxury and premiere housing projects which are not affordable for the people belonging to EWS and the LIG. The onus then falls on the government which has been the source of the welfare programs in this regard so far.

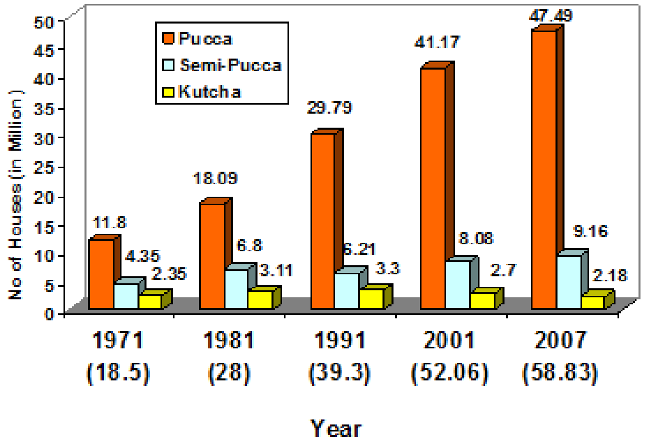

The projections suggest a shortage of about 19 million housing units by the year 2030. An increasing demand of housing units will be seen from a growing middle class, economically and otherwise which are affordable along with catering to the basic necessities. An undertaking of such a huge construction project will have two broad economic impacts. One, this would lead to significant investment in the Construction and Real Estate sector **Quality Of Housing Stock** which will lead to significant growth in the GDP, considering, these two sectors together contribute to about one-fifth of the GDP along with employing 267 industries, and being the fourth largest employer in the economy.

However, since the project is being almost wholly undertaken by the Indian Government it needs to keep the cost low, and promote private participation.

Key Problems:

Land Cost: Starting with land cost, only the land on the outskirts of cities is cheap enough. Private partners are hard to find in such areas because these locations are hard to market which

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

poses a risk to their profits, thus, acting as a hurdle. Connectivity is also a major challenge for these far away locations, and linkages to development activities taking place in the city need to be established. Along with this these areas should be developed enough to provide basic services like schools, colleges, hospitals, etc, which in itself is a huge project to undertake. A neighbourhood needs to be built. Connectivity and creating a complete living space requires investment in infrastructure as well. These housing projects won't be successful unless they provide these facilities.

Construction Cost: construction cost involves the cost of the material used & the construction process itself which involves labour and machinery. About 65% to 75% of the total cost of construction is spent towards building materials. Slowly gaining popularity is the technology based construction of precast projects. The costs under precast technologies are lower by a factor of 20% to 50%. The quality of the constructed structure is better and more durable. Along with the cost they save time too which is a major need for the affordable housing projects. The only catch is that in order to get the benefits of economies of scale a minimum of one million square feet needs to be built and it requires more skilled labor.

Affordability: With incomes as low as Rs.5,000a month for a family of 4, for the EWS bracket, and the high variability in income levels, affording a 300 sq. feet house that fall under this category becomes difficult, even though the cost of such houses are highly regulated. Even affording the houses under the slum rehabilitation programs with 225 Sq. feet houses is a feat the EWS aren't able to achieve. These are usually slum dwellers. The census of 2011 estimated the number of urban slum dwellers to be 17.4%, which amounts to one in six households. About 90% people living in the slums work in the informal sector without a steady flow of income. This puts even the renting options out of the question for a lot of developers.

India is in a state of deep inertia about the urgency ad scale of urban reforms. However, with the change in government and the new government's focus on infrastructure development new energy has been introduced in the affordable housing sector, although the focus remains creating more liveable spaces in the form of SmartCities Project. The SmartCities project details so far have not provided any clarity on the matter of Affordable Housing.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Governement Initiatives:

The main focus here is the rate at which slums are proliferating. To tackle this problem the government has been implementing supply side interventions such as the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) and the Rajiv Awas Yojana (RAY).

JNNURM was launched in 2005 aiming to construct 1.5 million units for the urban poor within a period of 7 years. With an outlay of Rupees 33,860 crores and Central Government subsidy of Rupees 18,500 crores the project has two missions:

1. Basic Services for the Urban Poor which ensures provision of basic public utilities such as water and health & education in low income segment in 65 Mission Cities
2. Integrated Housing and Slum Development Programme which provides the same services for cities and towns other than the Mission Cities.

"Slum Free India" is the idea behind **RAY** with inclusive and equitable access to basic civic infrastructure, social amenities and decent shelter for every citizen. It aims to encourage States/Union Territories (UTs) to tackle slums in a definitive manner, by focusing on:

- Bringing all existing slums, notified or non-notified (including recognised and identified) within the formal system and enabling them to avail the basic amenities that is available for the rest of the city/UA;
- Redressing the failures of the formal system that lie behind the creation of slums by planning for affordable housing stock for the urban poor and initiating crucial policy changes required for facilitating the same. (AHP-Guidelines, MoHUPA, 2013)

There have been targeted subsidies for the poor and vulnerable groups, loan assistance at below market interest rate for housing, creation of housing assets as part of employment and income generation programs. Affordable housing is also a part of Priority Sector Lending.

Along with stepping up the pace of infrastructural investment in affordable housing the government also needs to encourage rental housing as an option for the poorest of the poor. The overall government participation in affordable housing has been very weak with not enough investment and the lack of efficiency. Further, the government's flagship schemes like VAMBAY and RAY haven't been as successful with providing just 20% of the true redevelopment costs of slums.

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

These projects seem pale in comparison to the initiatives taken over time by some of the other countries like Singapore that provides public housing for more than 80% of its population using land monetization and interest rate subsidies. Every country has faced the issue of rapid urbanisation and incommensurate housing space. Comparison of policies undertaken to deal with this problem provides a key understanding to pave a way for India.

However with the new Smart Cities Project, perhaps the increase in income and employment along with more efforts to eliminate slums housing might be provided for the slum dwellers as well.

The government has introduced the AMRUT scheme with an outlay of 50,000 crore rupees which has affordable housing for all as a target.

Looking at the data available we can see that given the magnitude of the housing shortage and budgetary constraints of both the central and state Governments, it is clear that public sector efforts will not suffice in fulfilling the housing demand. Even though a few private businesses have ventured into this property segment a majority are still reluctant to cater to the mass housing demand given the low profit margins which seem unviable in light of the high risk involved due to the restrictive laws, archaic planning, control regulations, high transaction costs, long winding process and a fragmented market.

The Government needs to incentivise private investment in the sector either through tax benefits or different accounting treatment of depreciation or Research and Development support which might help reduce cost.

For the home-buyers there needs to be better discovery mechanism, in this regard government's emphasis on Digital mode of operation can be helpful, by creating a centralised Database for all Affordable Housing projects available in the area along with the cost involved. Alongside they need to improve on the efficiency of their own schemes. Not-for-profit organisations' and cooperatives' potential to increase the available stock of affordable housing needs to be explored. However to enable this, governments have to actively introduce funding, policy and regulatory strategies that enable such providers to develop affordable housing.

There is a need to develop organisations such as rental management companies that help keep an account of available rental units for the EWS and LIG along with taking over rent collection

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

responsibilities of the government. Introducing mortgage funds would also help bridge the funding gap.

Conclusion:

Quoting Rakesh Mohan, Deputy Governor of the RBI, in 2007 "…future national competitiveness and economic success will depend on the comparative efficiency of cities. Because housing is where jobs go to sleep at night, the quantity, quality, availability and affordability of housing becomes a key component in national economic competitiveness", it can be said that the growth we keep expecting and planning for wouldn't reach its potential if the engines of growth, our demographic, do not have the basic necessities, housing being a frontrunner.

In the recent decade, India has achieved strong rates of economic growth and rising incomes, but the question of sustainability remains. With the current surge in demand for housing, access to basic services remains indignant posing an unpleasant foundation to India's aspiration for social cohesion. Urban Indian life stands to deteriorate which may also lead investors to turn away from chaotic environments for their businesses. A lasissez-faire approach cannot succeed and a proactive attempt to address the issue of urbanisation is needed to maximise economic opportunities.

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 35102017
Peer–Review Refereed Research Journal

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

बाजारवाद का प्रसार और स्त्री लेखन

डॉ. कमलिनी पाणिग्राही, विभागाध्यक्ष, हिन्दी
ई. डी. महिला महाविद्यालय
कटक, ओडिशा
ई-मेल : dr.kpanigrahi@gmail.com

बाजार के समय में रहते हुए बाजार की सत्ता से इंकार नहीं किया जा सकता | समकालीन समय का सच यही बाजार है | आज मनुष्य सभ्यता के उस भोड़ पर खड़ा है जहाँ चहुँ और बाजार की वाजार है | समकालीन दौर में वस्तुएं बोलती है और इंसान चुप खड़ा है | समय के माथ-माथ बाजार में गति और चमक भरती जा रही है | इससे वस्तुओं को बढती तादाद के माथ-माथ वस्तुओं की टकराहट महासमुद्र तैयार कर रही है | विश्व बाजार के आतंक ने स्वाभाविक और ममान्य को हाशिए पर डेल दिया है| समकालीन दौर में बाजार ने सम्पूर्ण समाज को आगोश में ले लिया है | ऐसा असंवेदनशील और क्रूर समय समकालीन दोर से पहले कभी नहीं आया था, जब बाजार के नियम सामाजिक मूल्यों को ताक पर रखकर मनमानी कर रहें हों | आज ऐसा दौर हैजब बेचने वाना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है | बाजार में सिर्फ खरीदने और बेचने वले होते है और मानवीय मूल्य को ताक पर पैत्का जा रहा है | सारी मानवीय संवेदनाएं जाने-अनजाने आहिस्ता-अनिता बाजार को संवदनाओं में तबदील होने लगी हैं, आज कीमत के परे किसी भी चीज का न तो मूल्य है और न ही अस्तित्व. केदारनाथ सिह के अनुसार- "लगभग छह भी साल पहले कबीर ने इस चुहिया को एक हाट कहा अति 'पूरा किया बिसाहुणा, बहुरि न आर्यों हटूट' आज कबीर की बाणी सौ प्रतिशत सच लग रही है, जब हम समाज और संबन्धी को बाजार में तबदील होते देख रहे हैं |

पिछले पंद्रह-बीस वर्षों की अवधि में लिखे गए उपन्यासों में लेखिकाओं ने बाजार की विरूपताओं का पर्दाफाश किया है | उन्होंने बाजार की अमानवीयता क्रो यस्त-दर परत उघाड़ा है | इनका मानना है कि ऐसा असंवेदनशील समय आज से पहले कभीदेखने क्रो नहीं मिला था, जब बाजार के नियम सामाजिक मूल्यों पर इतने हावी हुए हों | समकालीन स्त्री-लेखन बाजार के प्रसार और ताकत से बेहद खौफजदा, साथ ही वितित और सजग भी |

अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ आम व्यक्ति के लिए बाजार का तिलिस्म रचकर मनुष्य को न केवल मनुष्य रहने देती है न व्यक्ति वरन उसे हृदयहीन मशीन में तबदील कर उत्पाद बनारही है | डॉ. रोहिणी अग्रवाल के अनुसार-' 'बाजार को फतह इंसानी विवेक को पूरी तरह कुचल डालने में निहित है'| '**दौड़**'

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 35102017
Peer–Review Refereed Research Journal

ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

उपन्यास में ममता कालिया ने बाजारवाद की इसी अंधी दोड़ का वर्णन किया है कि समकालीन बाजार व्यापक और आकर्षक होकर मनुष्यता का हनन कर रहा है | कथित उदारीकरण ने भारतीय बाजार की ताकत प्रदान कर युवावर्ग के लिए सिमसिम का दुवार खौल दिया है | बाजार के वशीभूत होकर युबा आत्मिक रिश्तों को भी भूलाते जा रहै है लेखिका के अनुसार- "जिन चु/शल-प्रतिभाओं ने यह कमान संभाली है उन्होंने कार्यक्षेत्र में तो खूब कामयाबी याई है, पर मानवीय संबंधी के समीकरण उनसे कहीं ज्यादा खिंच गए हैं, तो कहीं ढीले पड़ गए हैं|

माँ-बेटे के गहन रिश्ते में भी बाजारीकरण घुस आया है| समकालीन दोर में व्यक्ति महंगा निपट देकर हल्का होना चाहता है | गिपटों को कीमत पर रिश्तों की कीमत आँकी जा रही है | पवन की भी रेखा जब उससे मिलने सोराष्ट्र गई तो पवन व स्टेला रेखा के लिए निपट में शीशे की महंगे दाम की चामर लेकर आते है ताकि भी को खुश किया जा सके | रेखा उसे लेने से इंकार करती है, तब असली चेहरा, जो बाजारवाद रने आप्लावित है, सामने आता है | पवन के शब्दों में - " आपको पता है हमारे तीन हजार रूपये इस निपट पर खर्च हुए हैं | इतनी कीमती चीज को कोई कद्र नहीं है आपकी |

इसमें पवन का भी दोष नहीं है, साहित्यिक अभिरुचियों से चुका राकेश और रेखा को बाजार के ग्लैमर का ऐसा प्रभाव केता है कि अपने बच्चों को पा तरह से बाजारवादी व्यवस्था का अंग वना देते है | इसी कारण दोनों पीहियो की सोच में गहरा अंतर आ जाता है जिसकी परिणति राकेश और रेखा की अकेलापन एवं असहायता में होती है, दूसरी तरफ पवन व सघन की महत्वाकांक्षा उम्हें मानवीय मूल्यों से विलग कर देती है|

'दौड़' बाजारीकरण के चुग में परिवारिक संबंधी के बदलते समीकरण की कहानी है | पवन व स्टैंला के संबधि जैसे नहीं है जैसे कि राकेश व रेखा के है बल्कि उनके रिसते पूंजीवादी चेतना से ताकत लेते प्रतीत हॉ रहै है प्रो. भूत्युजंय उपाध्याय के अनुसार- "दौड़ मानवीय संबंधों के बाजारीकरण की दास्तान है, जहाँ जन्मपत्रिया कंप्यूटर से मिलाई जाती है और पति-फ्लो के संबंध तौल होते हैं | इस डीलिंग में प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण जैसे मानवीय मूल्यों का छाई रोल नहीं है|

समकालीन दौर में बाजार का आदर्श अब बाजार नहीं रह गया है, जहाँ व्यक्ति बुनियादी जरूरतों को चीजों को मुहैया करवाने के लिए इकटठे होते थे, बल्कि आज मनुष्य कर्तव्यों, मूल्य मान्यताओं और जरूरतों को नजरअंदाज करता हुआ बाजार के नियमों से संचालित होने लगा है | आज बाजार का आदर्श बहुराप्टीय कंपनियों तय कर ही है जिन्होंने आर्थिक साम्राज्यवाद का रास्ता विकास को गारन्टो पाकर खोल दिया है | समकालीन बाजार नव साम्राज्यवाद की आयोजित नीति है, जो पूरे विश्व की मण्डी में तबदील करना चाहती है |

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

डॉ. रोहिणी अग्रवाल के अनुसार- "ज़रूरत पड़े तो कच्चे माल के आयात को अण्डा जरूरत का चेहरा बदले तो नैया माल के खपत की मण्डी बाजार के तिलिस्म में लोगों को कंसाए रखने और 3 उसे छोड़कर बाहर निकल आने की जदूहौजहद आज के चुग का यथार्थ है |

बहुराष्ट्रीय कंपनियों हमेशा ही अपने माल को खपत के लिए मौर्क की तलाश में रहती है, यह मौका चाहै आजादी की वर्षगाँठ जैसे महान मूल्यों का ही क्यों न डो, उम्हें तो सिर्फ अपना कायदा दिखाई देता है | 'कलिकथा वाया बाइपास' उपन्यास में आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर किशोर का बेटा हरे रंग की फ्रीडम फोर्ड की चाबी किशोर को थमाता है तो उसे गहरा धवका लगता है कि बहुराष्ट्रपैय कंपनिया आजादी जैसे महान मूल्य की तुलना एक गाडी से कर रही हैं और किस तरह से तिरंगे झगडे की रंग वली गाडियों ऐन आजादी की वर्ष गांठ के सौर्क पर लोंच कर उन नृत्यों का हनन कर रही है | जो अपनी मातृ भूमि के लिए लोगों के दिलों में विद्‌यमान होते हैं | वह कहता है कि एक चाची से स्वतंत्रता मिल जाती तो इतने लोगों को जान देने को क्या जरूरत थी | मार्केट कंपनियों की इस खबर को किशोर ने कुछ ही दिन पहले अखबार में पढा था | उसने सोचा था -' है फोर्ड कम्पनी की गाडी मार्केट में बिक नहीं रही है | बहुत कम्मीटिशन है इस तरह की गाडियों के बीचा इसलिए ये सब तरकीबें हैं '|

समकालीन रबी लेखन व्यापक मानवीय दृष्टि का परिचय देता हुआ, अपनी लेखनी के माध्यम से समय और समाज का विश्लेषण कर रहा है | ' कोशा' 'दौड' एक बेक के बाद, कलिकथा वया बाईपास' आदि उपन्यासों में बाजारतंत्र का पर्दाफाश करते हुए तर्क देती है | कि इस बाजार ने भारतीय समाज को एक उपभोग समाज (Consumption Society) में तब्दील कर दिया है|

बाजार ने स्वी को सरिता का प्रलोभन देकर उसे वस्तु में तब्दीलकर दिया है | बाजार के इस कारोबार में बहु राष्ट्रपैय कंपनियों के लिए उपभोक्ता तैयार करने मेंमदद करती हैं | आज स्वी विशिष्ट स्थिति प्राप्त करने के प्रलोभन में बाजार के चुंगल में फसतीजा रही है | 'आंबा' उपन्यास में नमिता के माध्यम से लेखिका बाजारवाद के अवमूल्यन सेपरिचित कराती है कि आज वह अंधाधुंध गति से अपने भीतर पसरी बाजार को शक्तियों के हाथोंबिक रही है |

संजय कनोई आभूषण व्यवसाय में अत्यधिक फायदे के लिए नमिता को मोहराबनाता हुआ, दस हजार रूपये देकर विदेशी बाजार के लिए प्रदर्शन की वस्तु बना डालता है- "फोन करने के पीछे विशेष प्रयोजन यह था कि विदेशी बाजार के लिए एंटीक आभूषणों कामैं एक कैटलोग बनवाना चाहता हूँशीघ्र ही | इस काम के लिए हमें एक खूबसुरत मांडल कोतलाश है, जो भारतीय छबि का प्रतिनिधित्व कर सकै | निर्मला ने सुझाव दिया और मुझे भी लगाकि हमारी तलाश का अंत तुम हो |

बाजार के प्रसार के साथ स्वी की स्थिति में गिरावट आई है वहदिन प्रतिदिन देह में रिड्यूस होती जा रही है | समकालीन दौर में भले ही वह अपने अधिकारोंको समझने लगी है, फिर भी वस्तु से बढकर

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

Vol. II, Issue XXX – October - 2017
Article ID # 35102017
Peer–Review Refereed Research Journal
ISSN No. 2395-6941
Website: http://www.umrjournal.com/

कूछ भी नहीं है | आंवा उपन्यास में सिद्धार्थ नमितासे कहता है- "देखो पोर्टफोलियों मैं तुम्हारा तैयार करवा दूंगा | फीस की शक्ल भर बदलजायेगी | पोर्टफोलियों वनाने की एवज में तुम्हे मेरे साथ देहिक संबंध रखने होंगे |

बाजार में जगह बनाने के लिए रबी के लिए यह जाना बहुतजरूरी है कि देह पर अधिकार और मस्तिष्क नियंत्रण के बिना, वह बाजार के नियमों को अपनेअनुकूल नहीं ढाल सकती | आज बाजार को नियामक शक्तियों के हाथ का खिलौना बन स्वीअपनी शर्तों को बना...बदल भी रही है | 'दोड़' उपन्यास की स्टैला बाजार के नियमों का शिकारहै, फिर भी परम्परागत अवधारणाओं को छोड़कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में सफलहुई है |

रेखा कस्तवार के अनुसार - "बाजार ने का एक और शोषण किया है, तो उसे बाहर निकलने के अवसर भी दिये है, निरोधकों के बाजार ने उसे देह में बदला है तो देह से मुक्ति भी दी है, सौंदर्य प्रतियोगिताओं ने स्वी को सेल्स पात्रों बनाया है तो पैसे कमाने के अवसर भी सौंपे हैं | स्वी इस संक्रमणकाल का उपयोग पूँजी के साम्राज्य में सेंध लगाने के लिए कर रही है | बाजार में आकर स्वी ने परम्परागत सरंचना से मुक्ति के रास्ते जुटाए है |

बढ़ते बाजारीकरण ने शिक्षा व संस्कृति को भी बाजारी चीज बना दिया है | समकालीन दोर में शिक्षा दी नहीं जाती बल्कि बेची जा रही है | शिक्षा के निजीकरण के कारण स्कूलों में महंगी फीस देना गरीब आदमी के लिए असम्भव है | संस्कृति किसी भी समाज के खान-पान, बेश-भूष साहित्य, कला, संगीत नृत्य खेलकूद की समग्रता का नाम है, परन्तु इन सब पर बाजार का जोरदार हमला हो रहा है | मुनाफे और पैसे के लिए सब कूछ तोडा-मरोड़ा जा रहा है | समकालीन व्यवसायिक संस्कृति हर चीज का मोल-भाव कर रही है |

बाजार के माध्यम से अमेरिका जैसी महाशक्तियों संस्कृतिक बला कर रही हैं | ब्रज कुमार पाण्डेय के अनुसार -" ' व्यवसायिक संस्कृति समाज की हर चीज को बिकाऊ बनाती है वह समाज की जरूरत को नहीं मुनाफे की जरूरत को व्यक्त करती है | बाजार तंत्र की विशेषता यह है कि उसे खरीद-बिक्री करने वालों की जरूरत है, सबसे ज्यादा खरीदने वालों, की जो खरीदने की क्षमता नहीं रखता वह आदमी बाजार तंत्र के लिए एक दम बेकार है |'

"एक ब्रेक के लद' उपन्यास में वीबी. बाजार की शक्तियों का आन्तरिकीकरण करते हुए बाजार में ही आत्म सार्थकता की तलाश करता है | अपने फायदे के लिए वह छाई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता | चौरहिया के साथ फिर रने जुड़ना उसके आत्मीय संबंध न होकर सिर्फ मोटा पैकेज मिलना है वह स्वयं कहता है - "अब नौकरी की दुनिया खरीददारों की मार्केट नहीं, बेचने वालों की मार्केट है, जो बीस हजार की नौकरी छोड़ता है वह जानता है कि पचीस हजार की नौकरी उसके लिए तैयार है |

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

मनुष्य की सुविधाभोगी प्रवृति बाजारवाद को बढावा है रही है| इसी सुविधा भोगी प्रवृति के कारण केवी पत्नी की तरह सम्पूर्ण समाज बाजार का सुनाम बनता जा रहा है| बहुरारुट्रीय कंपनिया इंसान की इस कमजोरी क्रो पहचान सिके मुनाफा कमाना चाहती है| अपने हाथों से निकाला जूस पिलाने के लिए किस तरह कं.ची की पत्नी जूसर सैट खरीदने के लिए तैयार हो जाती है|

लुभावने सपने दिखाकर कंपनियों किस तरह इंसान की मानसिकता को पंगु वना रही है| उपन्यास में - "एक पात्र की पत्नी बेहद खुश थी कि लगभग बिना मेहनत के ताजा जूस कं६त्नी के लिए खुद निकाल सकै| कं.बी खुश थे कि वे एक ऐसी मशीन बना सकेंगे जो अभी तक इण्डिया में किसी ने न बनाई, न देखो है| यह मशीन इण्डियन स्काई कांप की सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों में से एक साबित हुई '| सुख सुविधाऒं का सामान किसी भी प्रकार से आए, यही बाजारीकरण का पहला लक्ष्य है| बाजारवाद मानवतावाद पर हावी हो गया है, जिसने इंसान कौ इंसानी ज़ज्जातों जरूरतों को ठुकराकर, उसे लालची बना दिया है| बाजार व बाजार से जुडे लोग सिर्फ अपने फायदे का ध्यान रखते है, पैसे के लालची लोग देश-जीया के नुकसान की परवाह नहीं करते हैं| जब रंगनाथन कं.ची को ज्योतिष-ग्रह-रत्न, विज्ञान और आईटी. के चुग में इण्डिया को पीछे धकेलने की राजिम बताते है तो रंगनाथन की बात सुन के कं.बी के दिमाग में सिके यही बात उठती है|'खरीदने वाले चाहे तो खरीद हमें तो सिर्फ कूछ बेचने से मतलब है| कोई अंधविश्वासों हो, तो उससे हमें क्या?

बाजारवाद का सर्वप्रमुख आधार सपने और लालसाएँ बेचना है| बाजार प्रबंधन में यह सिखाया जाता है कि किम प्रकार किसी उत्पाद के लिए लालसा जगाईं जाती है| बहुराष्ट्रपैय नियमों में शेधि और विकास प्रखण्ड है जिसमें निरन्तर यह शोध चलती रहती है कि आगामी दस-बीस वर्षो में अमुक वस्तु, उत्पाद आदि की किस प्रकार मांग पैदा की जा सकती है| उपन्यास में कं.बी.शश्कर अक्षर इसी तरह के नुरखै आजमाते हैं|

समकालीन दोर में बाजारवाद का प्रसार उद्योग, कृषि, शिक्षा सभी क्षेत्रों में फैल चुका है| इससे सभी प्रसन्न है कि सुखों में तेजी से विकास होता जा रहा है| जो समान कल तक केवल अमीर आदमी तक सीमित आ, आज वह गरीब की पहुंच में है| बाजार से व्यक्ति सपने खरीदते है और सपनों में रहते हैं| हर की शहर में बाल आ गए है कपड़ा बाजार पिछड़ गया है, सब्जी मण्डी पिछड़ गई है, केश आ गए है जो गरीब वर्ग की रोजी-रोटी को छीनतें जा रहे हैं|

आज न तो बच्चा-बच्चा रह गया है और नही बूढा-बूढ़| बचपन जैसी नैसिंर्मिक भावना को भी बाजार ने सुनि लिया है| बूढे तिरस्कृत या युबा बनने के प्रयास में विदूषक बनते जा रहे हैं| पति-पनी मात्र यंत्र के पुर्जे रह गए है, उगे भाव पैसा कमाना जानते हैं|

© Universal Multidisciplinary Research Journal (Online)

मीडिया के माध्यम सै बाजारवाद हर घर में प्रविष्ट होकर सुख के लुभावने सपने दिखा रहा है, यही बाजार की इच्छा है| कबीर ने बहुत पाले बाजार रूपी भाया के बारे में कहा था 'माया महाठगिनी हम जानी, तिरगुन फाँस लिये कर छोले, बीले मधुरी बानो|

सन्दर्भ सूची :

1. संपादकीय 'खरी-खरी बात' से, 'युद्धरत आम आदमी' संपा. रमणिका गुप्ता पूर्णांक 108, 2011
2. निवेदिता मेनन . 'नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एवं मुद्दे ' संपादक: साधना आर्य , निवेदिता मेनन , जिनी लोकनीता,
3. 'सामायिक मीमांसा' संपा. विजय कुमार मिश्र:अंक 1, वर्ष 4, जनवरी-जून-2011
4. जर्मेन ग्रीयर: 'द फीमेल यूनक'
5. नाओमी वुल्क, 'फायर विद फायर
6. महानगर में गिलहरी (कहानी), आनन्द हर्षुल, अन्यथा, अंक 5, पृ. 103
7. नया ज्ञानोदय, सं. रवीन्द्र कालिया, अंक 90, अगस्त 2010, पृ. 48
8. उद्धृत लेख रमैया की दुलिहन ने लुटा बाज़ार, डॉ. शिवकुमार मिश्र, सम्प्रेषण, अंक 133, वर्ष 39, 2004, पृ. 59-60
9. शाल्मली, नासिरा शर्मा, किताबघर प्रकाशन, 1994, पृ.सं. 25